Dr. S. S. Pandey

संपूर्ण विश्लेषण

जाति आधारित जनगणना

Caste Based Census

1

THE HINDU

Updated - March 01, 2024 12:53 am IST
Published - February 29, 2024 09:20 pm IST - Bengaluru

OBC panel submits caste census report finally

The long-pending final report of the Socio-economic and Educational Survey (caste census) of Karnataka was submitted to Chief Minister Siddaramaiah here on Thursday.

2

THE HINDU

Updated - January 20, 2024 07:03 pm IST
Published - January 20, 2024 12:41 pm IST

Caste census will help improve living standards of BCs, SCs and STs, says Andhra Pradesh Revenue Minister

Andhra Pradesh Minister for Revenue Dharmana Prasada Rao has directed the district administration to complete the caste census by the end of this month.

3

2 अक्टूबर 2023

बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी

4

THE HINDU

October 02, 2023 05:02 pm | Updated 06:46 pm IST - New Delhi

Bihar caste survey results may open door to challenging 50% ceiling on reservations

The Bihar caste survey showed that the Other Backward Classes and the Extremely Backward Classes between them constituted 63% of the State's population

The caste survey undertaken by the Bihar Government, results of which were made public on Monday, may open the door to challenging the 50% ceiling on reservations in jobs and educational institutions currently in place, as also a recalibration of the Mandal politics of the 1990s, say observers.

5

Leading the Debate Since 1984

FRONTLINE

The release of the Bihar caste survey report, which puts the State's backward castes at 63.14 per cent, threatens the BJP's carefully nurtured "Hindutva unity" and brings caste right back into the political fray.

6

लालू प्रसाद यादव
अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल

"When our government will be formed in 2024, we will carry out a caste census in the entire country and will out from power the anti-Dalit, anti-backward, anti-extremely backward, and anti-Muslim BJP."

लालू प्रसाद यादव

7

डॉ. राम मनोहर लोहिया
नेता, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

sansopa ने बांधी गांठ,
पिछड़े पावे 100 में 60
राज-पाट है किसके हाथ,
अंग्रेजी और ऊंची जाति

डॉ. राम मनोहर लोहिया

8

बिहार जाति जनगणना :
रिपोर्ट

9

Distribution of social groups by Religion

Total population	130,725,310	
Religion	81.99%	Hinduism
	17.70%	Islam
	0.08%	Buddhism
	0.06%	Christianity
	0.01%	Jainism
	0.01%	Sikhism
	0.13%	Others

10

11

Distribution of social groups by category

- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) (36.01%)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (27.12%)
- अनुसूचित जाति (SC) (19.65%)
- अगड़ी जाति (FC) (15.52%)
- अनुसूचित जनजाति (ST) (1.68%)

12

Distribution of social groups by Caste

S N	Caste	Population	Percentage
1.	Yadav (Ahir, Gowala, Gora, Ghasi, Mehar and Sadgop)	18,650,119	14.2666%
2.	Kushwaha (Koeri)	5,506,113	4.212%
3.	Dangi	336,629	0.2575%
4.	Mali	349,285	0.2672%
5.	Kunjra	1,828,584	1.3988%
6.	Kurmi	3,762,969	2.8785%
7.	Dhanuk	2,796,605	2.1393%
8.	Sainthwar	20,505	0.0157%

13

S N	Caste	Population	Percentage
9.	Brahmin	4,781,280	3.6575%
10.	Teli	3,677,491	2.8131%
11.	Mallah (Nishad)	3,410,093	2.6086%
12.	Gangota (Gangaputra)	648,493	0.4961%
13.	Nonia	2,498,474	1.9112%
14.	Kanu	2,892,761	2.2129%
15.	Bania	3,026,912	2.3155%
16.	Bhumihar	3,750,886	2.8693%

14

S N	Caste	Population	Percentage
17.	Rajput	4,510,733	3.4505%
18.	Dushadh (Dhari, Dharahi)	6,943,000	5.3111%
19.	Musahar	4,035,787	3.0872%
20.	Kayastha	785,771	0.6011%
21.	Ravidas (Mochi, Ravidas, Rohidas, Charmkar)	6,869,664	5.255%
22.	Chandravanshi (Kahar, Kamkar)	2,155,644	1.649%
23.	Nai	2,082,048	1.5927%
24.	Pan, Sawasi, Panar	2,228,343	1.7046%

15

S N	Caste	Population	Percentage
25.	Kumhar (Prajapati)	1,834,418	1.4033%
26.	Barhai (carpenter)	1,895,672	1.4501%
27.	Dom, Dhangadh, Bansfor, Dharikar, Dharkar, Domra	263,512	0.2016%
28.	Dhobi (Rajak)	1,096,158	0.8385%
29.	Nat	105,358	0.0806%
30.	Barai, Tamoli, Chaurasiya	616,092	0.4713%
31.	Hari Mehtar, Bhangi	255,582	0.1955%
32.	Rajbhar	224,722	0.1719%
33.	Sonar	893,276	0.6833%

16

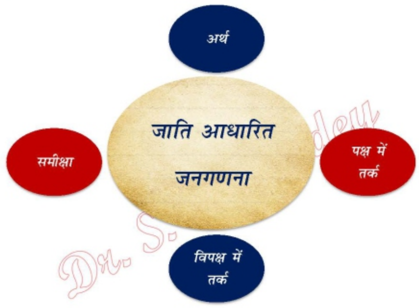

17

जाति आधारित जनगणना का अर्थ

Meaning of Caste Based Census

18

किसी भी राज्य या क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या का जातिवार विवरण को 'जाति जनगणना' (Caste Census) या 'जाति आधारित जनगणना' (Caste Based Census) कहा जाता है।

19

जाति आधारित जनगणना : ऐतिहासिक विश्लेषण

Caste Based Census: Historical Analysis

20

1. 1881 से 1931 तक भारत में जाति आधारित जनगणना सम्पन्न

   तत्पश्चात् 1951 से 2011 तक केवल SC और ST की गणना

Dr. S. S. Pandey
KGS IAS

Sir Herbert Hope Risley

Census Commissioner of India

As long as there is caste there will be no India

Sir Herbert Hope Risley

(The People of India)

21

Bindheshwari Prasad Mandal

Former, Chief Minister of Bihar

2. 1980 में OBC के अंतर्गत आने वाली जातियों की जनगणना (पायलट स्टडी के रूप में) सम्पन्न (1931 की जनगणना के आधार पर)–

और मण्डल कमीशन द्वारा OBC के रूप में 52% जनसंख्या तथा 1257 जातियों की पहचान–

तथा OBC को 1990 में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और 2006 में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण

22

3. स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना (Socio-Economic Caste Census) 2011 में प्रारंभ और 31 मार्च 2016 को समाप्त

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस जनगणना के निम्न उद्देश्य बताये गए–

23

(i) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की जानकारी प्राप्त करना

(ii) विभिन्न जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना

(iii) इन सूचनाओं के आधार पर सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं सम्पादन करना

24

4. 2011 की यह जनगणना संसार की सबसे मँहगी जनगणना (5000 करोड़ खर्च) परन्तु आँकड़ा अभी तक जारी नहीं

5. कई राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा आँकड़ा जारी करने की माँग

25

6. 2 अक्टूबर, 2017 में, केन्द्र सरकार द्वारा रोहिणी आयोग का गठन और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के और वर्गीकरण पर बल

31 July, 2023 - OBC पर रोहिणी आयोग ने सौंपा रिपोर्ट

26

7. सितम्बर 2018 में, भारत सरकार द्वारा 2021 की जनगणना में पुनः OBC की जनगणना कराने की घोषणा

8. 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को– जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधान सभा और विधान परिषद् में पारित

27

9. सितम्बर 2020 को– 2011 की जाति आधारित जनगणना के आँकड़े 'केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' को सौंपे गए ताकि उनका वर्गीकरण एवं उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सके

28

10. 10 मार्च 2021 को– केन्द्र सरकार ने राज्य सभा में स्पष्ट किया कि– सरकार 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं करेगी

29

11. 23 सितम्बर 2021 को– केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके स्पष्ट किया कि, जातीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी करने में कठिनाई है क्योंकि आँकड़ों में बहुत त्रुटियाँ हैं और 2021 में जाति आधारित जनगणना कराना संभव नहीं है

30

12. 8 अक्टूबर 2021 को, तेलंगाना विधान सभा में तथा 23 नवम्बर को; आंध्र प्रदेश विधान सभा में 2021 में OBC की जातिवार जनगणना कराने हेतु माँग को लेकर प्रस्ताव पारित

31

13. 2 जून 2022 को– बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार में अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी

14. जनवरी 2023 को– बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण दो चरणों में प्रारंभ–

- ✓ प्रथम चरण - 7 जनवरी से 21 जनवरी
- ✓ द्वितीय चरण - 15 अप्रैल से 15 मई

32

15. 4 मई 2023 को बिहार हाई कोर्ट द्वारा जनगणना पर रोक और 1 अगस्त 2023 को जनगणना कराने की अनुमति

THE HINDU

August 01, 2023 01:31 pm | Updated 08:10 pm IST

Patna High Court upholds continuance of ongoing caste-based survey in Bihar

Court finds State's action 'initiated with due competence', and 'not having violated the rights of privacy of the individual especially since it is in the furtherance of a 'compelling public interest''

33

16. 2 अगस्त 2023 - जाति आधारित जनगणना पुनः शुरू और 6 अगस्त 2023 को जनगणना का कार्य पूर्ण, परन्तु यह मामला SC में और 3 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित

17. 2 अक्टूबर– 2023 बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी

34

18. 8 नवंबर 2023 - बिहार कैबिनेट द्वारा एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए मौजूदा कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

(20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द)

35

19. 19. जनवरी 2024 - आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना संपन्न।

प्रथम चरण - 19 जनवरी से 28 जनवरी

द्वितीय चरण - 29 जनवरी से 2 फरवरी

(जून 2024 - चन्दबाबु नायडू द्वारा रिपोर्ट को रोक दिया गया)

36

20. 29 फरवरी 2024 को कर्नाटक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जाति जनगणना रिपोर्ट सौंपा गया।

(जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा का निर्णय)

37

जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क / लाभ

Advantages of Caste Based Census

38

1. जाति प्रधान भारतीय समाज में, विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति स्थिति की जानकारी संभव

39

2. विभिन्न जातियों की सही संख्या व स्थिति के आंकलन से, उनके लिए समूचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन संभव

40

41 3. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्रा व प्रकृति की पहचान व इनके लिए समूचित कार्यक्रम बनाना संभव

42 4. आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण संभव (स्वतंत्रता के बाद केवल SC & ST को आरक्षण और 1951 से केवल SC & ST की गणना)

43 5. सामाजिक न्याय से युक्त विकसित एवं आधुनिक भारत का निर्माण संभव

44 **जाति आधारित जनगणना के विपक्ष में तर्क / हानि**

Disadvantages of Caste Based Census

45 1. विभिन्न जातियों के मध्य विद्वेष की भावना में वृद्धि तथा सामुदायिक सौहार्द्रता कमजोर

46 2. सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, जाति बदल कर दर्ज करवाने की संभावना

47 3. गलत सूचना से समानता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित

48 4. आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों में संघर्ष व तनाव में वृद्धि की संभावना

49 5. जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा और लोकतंत्र को खतरा

50 6. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित

51

समीक्षा

Evaluation

52

निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं...,

परन्तु भारत जैसे जाति प्रधान देश में, जहाँ जाति व्यवस्था कुछ परम्परागत स्वरूप तथा कुछ नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरन्तरता को बनाये हुए है और आरक्षण हेतु सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील है, आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर जाति आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

53

अतः निष्कर्ष है कि–

समकालीन भारत में जाति आधारित जनगणना, कुछ हानियों के बावजूद आवश्यक एवं प्रासंगिक है,

क्योंकि इससे न केवल विकास कार्यक्रमों को वांछित लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी, बल्कि आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण करके सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो पायेगी।

54

जाति आधारित जनगणना : संभावित प्रश्न

55

1. भारत में जाति आधारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए।

2. भारत में जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित आरक्षण के तार्किकीकरण में कहाँ तक सहायक हो सकती है? उपर्युक्त तर्क के साथ उत्तर दीजिए।

56

उत्तर संरचना

Part-I : आरक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य

Part-II : आरक्षण के संदर्भ में जाति आधारित जनगणना की हानि

Part-III : आरक्षण के संदर्भ में जाति आधारित जनगणना का लाभ

Part-IV : समीक्षा (लाभ पर केन्द्रीत)

Dr. S. S. Pandey

संपूर्ण विश्लेषण

भारत में जाति-राजनीति

(Caste Politics in India)

1

भारत में जाति-राजनीति :

महत्वपूर्ण तथ्य

Caste-Politics in India :

Important Facts

2

1. 2002 में राष्ट्रीय आयोग ने निर्वाचन में सुधार हेतु एक रिपोर्ट दी, जिसमें जाति आधारित चुनाव अभियान को रोकने की सिफारिश की गयी
2. 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में, प्रशासन में जातिवाद को रोकने पर बल दिया गया

3

3. 2013 में Allahabad HC द्वारा राजनीतिक दलों को जातीय आधार पर रैली निकालने को रोकने का आदेश दिया गया

4

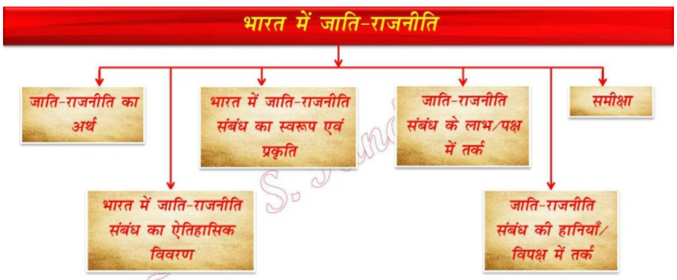

5

अंग्रेजी शासन काल में

जाति-राजनीति संबंध

Caste-Politics Relations during the British Rule

6

1. जस्टिस पार्टी - 1917 में रामासामी नायकर (पेरियार) द्वारा
2. द्रविड़ कझगम - 1944 में नायकर द्वारा अन्नादुरै के साथ
3. बिहार में 1937 में, यादव, कोइरी एवं कुर्मी द्वारा त्रिवेणी संघ का निर्माण

7

उत्तर भारत में

जाति-राजनीति संबंध

Caste-Politics Relations in North India

8

1. उत्तर भारत की सामाजिक संरचना
   Social Structure of North India
   ↓
   (i) समाज अगड़ी एवं पिछड़ी जातियों (Forward & Backward Castes) में विभक्त
   (ii) 1945-1970 के काल में उच्च जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण

9

(iii) 1970 के बाद मध्यवर्गीय जातियों (Middle Castes) का राजनीतिक सशक्तिकरण

(iv) 1980-1990 तक दलित जातियों (Dalit Castes) का राजनीतिक सशक्तिकरण

10

11

(v) 1990-2020 तक बिखराव (Scarcity) का काल-

- अलग-अलग जातियों के अलग-अलग नेतृत्व;
- एक ही जाति में कई नेतृत्व;
- जाति-राजनीति में नवीन समीकरण (New Equation) का निर्माण और विकास (Development) के साथ जाति-राजनीति संबंध

12

दक्षिण भारत में जाति राजनीतिक संबंध

Caste Political Relations in South India

13

1. दक्षिण भारत की सामाजिक संरचना

Social Structure of South India)

↓

(i) समाज ब्राह्मण बनाम गैर-ब्राह्मण जातियों में विभक्त, जैसे-

- तमिलनाडु- ब्राह्मण बनाम थेवार, चेट्टियार, मुदिलियार, बेलाला, बेन्नियार एवं नाडार

14

- आंध्र प्रदेश- ब्राह्मण बनाम रेड्डी, कामा, बेलामा एवं नायडू
- कर्नाटक- ब्राह्मण बनाम वोक्कालिंगा (बहुसंख्यक-16%), लिंगायत (बहुसंख्यक-17%), गौड़ा एवं कुरूबा
- महाराष्ट्र- ब्राह्मण (4%) बनाम मराठा (25%), कुनबी (माली एवं तेली के साथ 50%), महार (11%)

15

(ii) 1947-1970 तक- ब्राह्मणों के साथ-साथ मध्यवर्गीय जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण

(iii) 1970 के बाद- दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण

(iv) 1980-1990 में- बिखराव का काल

(v) 1990-2020 तक- नवीन समीकरण और विकास के साथ जाति-राजनीति संबंध विद्यमान

16

जाति-राजनीति संबंध - राजनीति में जाति

Caste-Politics Relations - Caste in Politics

17

अर्थात् राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता (Power) प्राप्ति हेतु राजनीति में जाति का प्रयोग

- विशिष्ट जाति (Particular Caste) के आधार पर राजनीतिक दलों (Political Parties) का निर्माण
- विशिष्ट जातियों को, उनके हितों को पूरा करने का वायदा
- जातीय आधार पर टिकट का बंटवारा

18

- चुनाव जीतने हेतु जातीय समीकरण का निर्माण [भाजपा, कांग्रेस, राजद, सपा, जनता दल आदि]
- सरकार में जातीय आधार पर मंत्रियों को प्रतिनिधित्व
- राजनीति में जातिवाद (Casteism in Politics) अर्थात् सरकार द्वारा विशिष्ट जातियों को सरकारी लाभ प्रदान करना

19

जाति-राजनीति संबंध - जाति में राजनीति

Caste-Politics Relations - Politics in Caste

20

अर्थात् जनता द्वारा सामाजिक-आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु राजनीति में जाति का प्रयोग

↓

- आर्थिक एवं राजनीति शक्ति (Economic and Political Power) प्राप्त करने हेतु दबाव समूह (Pressure Group) के रूप में जाति संगठनों (Caste Associations) का निर्माण

(जाट महासभा, गुर्जर महापंचायत आदि)

21

- राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति (Political and Economic Power) प्राप्त करने हेतु जातीय संघों (Caste Federations) का निर्माण
  (अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा आदि)
- जनता द्वारा जातीय आधार पर राजनीति में सहभागिता (Political Participation)

22

जाति-राजनीति संबंध के हानि / नकारात्मक पक्ष / विपक्ष में तर्क

Disadvantages of Caste-Politics Relation

23

1. राजनीति में तथा समाज में, जातीय निष्ठा (Caste Loyalty) को विकसित करके जातिवाद को बढ़ावा और आधुनिक समाज का निर्माण बाधित
2. राजनीति में जातिवाद (Casteism in Politics) से विकास की प्रक्रिया बाधित

24

3. विभिन्न जातियों के मध्य नकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा से जातीय-संघर्ष एवं तनाव (Caste Conflict and Tension) में वृद्धि, फलतः सामुदायिक सौहार्द्रता (Community Harmony) कमजोर

25

4. बहुसंख्यक एवं प्रभु जातियों (Dominant Castes) द्वारा, अल्पसंख्यक जातियों के हितों का हनन करके, समतामूलक समाज (Egalitarian Society) के निर्माण की प्रक्रिया बाधित
5. राजनीति में गुटबंदी (Factionalism in Politics) एवं राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) - फलतः लोकतंत्र कमजोर

26

जाति-राजनीति संबंध का लाभ / सकारात्मक पक्ष / पक्ष में तर्क

Advantages of Caste-Politics Relation

27

1. जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण द्वारा शक्ति संतुलन (Power Balance) स्थापित करके लोकतंत्र का विकास
2. निरक्षर जातियों को राजनीतिक जागरूकता (Political Awareness) एवं राजनीतिक सामाजीकरण (Political Socialisation) द्वारा, इनके राजनीतिक सहभागिता (Political Participation) एवं मतदान व्यवहार (Voting Behaviour) को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूती

28

3. राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, निम्न जातियों का सशक्तिकरण करके, समतामूलक समाज (Egalitarian Society) के निर्माण में सहायक
4. जाति संघ एवं जाति संगठनों (Caste Association and Caste Federation) के निर्माण द्वारा, दबाव समूह के रूप में शक्ति का विकेन्द्रीकरण (Decentralization of Power) करके लोकतंत्र का विकास

29

5. निम्न एवं कमजोर जातियों के द्वारा जातीय संगठनों के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति और सामाजिक न्याय (Social Justice) से युक्त भारतीय समाज का निर्माण

30

भारत में जाति-राजनीति संबंध : समीक्षा

Caste-Politics Relations in India: Evaluation

Dr. S. S. Pandey
KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

1. निश्चित रूप से भारत में जाति-राजनीति संबंधों ने दोनों तरह के परिणामों को उत्पन्न किया है

परन्तु इसके नकारात्मक परिणाम कई संदर्भों में लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय (Democracy and Social Justice) के लक्ष्य को दुष्प्रभावित कर रहे हैं

31

2. परन्तु... यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जाति प्रधान भारतीय समाज में जाति-राजनीति संबंधों को पूर्णतः समाप्त करना कठिन है।

साथ ही... भारतीय संविधान में भी जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण को असंवैधानिक नहीं माना गया है, इसलिए.....

32

..... इसलिए भारत में जाति-राजनीति संबंधों को पूर्णतः समाप्त करना न तो तर्कसंगत है और न ही व्यवहार में सफल,

इसलिए आवश्यक है कि– जाति-राजनीति संबंधों के नकारात्मक पक्ष को समाप्त किया जाय तथा ऐसे संबंधों को स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित करके इसके लाभों को प्राप्त किया जाय

33

3. जाति को नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग करने वाले दलों एवं व्यक्तियों को प्रतिबंधित करके, शिक्षा के प्रसार द्वारा लोगों की सोच को तार्किक बनाकर और अधिक से अधिक नागरिक समाज का विकास (Development of Civil Society) करके, जाति-राजनीति संबंधों के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है

34

भारत में जाति-राजनीति : संभावित प्रश्न

35

1. भारतीय समाज में राजनीति में जाति की भूमिका का परीक्षण कीजिए?

2. समकालीन राजनीति में जाति की बढ़ती हुई भूमिका को रोकने हेतु उपाय बताइए।

3. जाति व्यवस्था लोकतंत्र में बाधक है या साधक? स्पष्ट कीजिए।

36

4. "समकालीन भारतीय राजनीति में बढ़ रहे जातिवाद ने विकास को उपेक्षित किया है और लोकतंत्र को कमजोर किया है" चर्चा कीजिए।

5. "जाति ने यदि राजनीति हेतु आधार प्रदान किया है तो राजनीति ने जाति को नवजीवन दिया है।" स्पष्ट कीजिए।

37

Dr. S. S. Pandey

संपूर्ण विश्लेषण

खाप पंचायत एवं प्रतिष्ठा हत्या

Khap Panchayat and Honour

38

रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतिविरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं?

250/15/2020

39

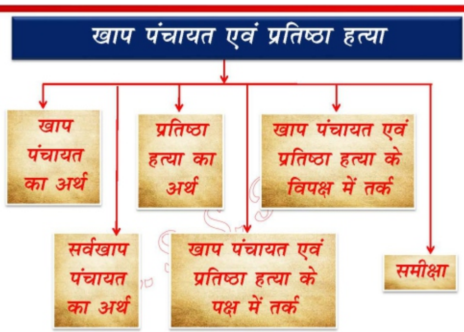

40

41

खाप पंचायत का अर्थ
Meaning of Khap Panchayat

46

वह हत्या जो परंपराओं, मान्यताओं, जातिगत नियमों आदि के उल्लंघन करने वालों को परंपरा संरक्षण (Preservation of Tradition) के नाम पर दी जाती है, प्रतिष्ठा हत्या कहलाती है।

42

सामाजिक प्रशासन की व्यवस्था हेतु निर्मित एक समूह जो मुख्यतः गोत्र समूह (Clan Group) होता है और जिसका संबंध जाट जाति (Jat Caste) से है व जिसके अंतर्गत कई गाँव शामिल होते हैं। ये गाँव वाले मुख्यतः एक ही गोत्र के होते हैं जिनके नाम से यह खाप पंचायत जानी जाती है, परन्तु इन गांवों में रहने वाले दूसरे गोत्र एवं जाति (Clan and Caste) के लोग भी इनमें शामिल होते हैं।

47

खाप पंचायत एवं प्रतिष्ठा हत्या के पक्ष में तर्क
Arguments in favor of Khap Panchayat and Honour Killing

43

सर्वखाप पंचायत का अर्थ
Meaning of Sarvakhap Panchayat

48

- परंपराओं की रक्षा एवं पहचान संकट का समाधान
- विवाह संबंधी निषेधों के पालन से रक्त मिश्रण से उत्पन्न होने वाली विकृतियों से रक्षा
- समुदायिक एकता (Community Unity) में सहायक

44

यह जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत (Supreme Panchayat) है। जिसमें सभी खाप भाग लेते हैं तथा जब कभी सामाजिक नियमों परंपराओं से जुड़ी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है या कोई आधुनिक समस्या भी उत्पन्न होती है, जिसका समाधान खाप स्तर पर नहीं हो पाता है तब सर्वखाप पंचायत का आयोजन होता है व उनका निर्णय मानना अनिवार्य होता है।

49

- समाजिक प्रशासन (Social Administration) में सहायक
- दबाव समूह के रूप में सक्रिय होकर शक्ति के विकेन्द्रीकरण में सहायक
- आधुनिक मुद्दों का समर्थन करके, आधुनिक समाज (Modern Society) के निर्माण में सहायक; जैसे- दहेज प्रथा का विरोध, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन आदि

45

प्रतिष्ठा हत्या का अर्थ
Meaning of Honour Killing

50

खाप पंचायत एवं प्रतिष्ठा हत्या के विपक्ष में तर्क
Arguments Against Khap Panchayat and Honour Killing

51
- परंपरा के नाम पर कट्टरतावाद (Fundamentalism) को बढ़ावा
- संवैधानिक मूल्यों के विपरीत व गैर-कानूनी
- आधुनिक समाज के निर्माण में बाधक
- पितृसत्तात्मकता (Patriarchy) का संरक्षण व लिंग समानता (Gender Equity) का विरोध
- अमानवीय गतिविधि

52
समीक्षा
Evaluation

53
1. हाल के वर्षों में खाप पंचायत की गतिविधियों में, प्रतिष्ठा हत्या जैसे मामलों ने इसे चर्चा का विषय बना दिया हैं क्योंकि यह गैर-कानूनी, अलोकतांत्रिक एवं अमानवीय है, इसलिए इसमें संलग्न लोगों को कठोर दण्ड देना चाहिए, पीड़िता को संरक्षण देना चाहिए और ऐसे निर्णयों को रोका जाना चाहिए।

54
2. खाप पंचायत की इस नकारात्मक भूमिका को देखते हुए यह प्रश्न स्वभाविक हो जाता है कि क्या इसे पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए?

इस संदर्भ में निष्कर्ष है कि, इस प्रकार के पंचायत को पूर्णतः समाप्त करना न तो तर्कसंगत है और न ही व्यवहारिक रूप से संभव है इसलिए इसके नकारात्मक कार्यों पर कठोरता से रोक लगाते हुए, इसके सामूहिक ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में प्रयोग किया जाना चाहिए।

55
जैसे- कन्या भ्रूण हत्या, दहेज का विरोध, स्त्री शिक्षा आदि के पक्ष में इसे जागरूकता का मंच बनाकर, इसके लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, इसका प्रयोग हाशिये पर चले गये किसानों को लाभबंद करने तथा वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्षों का विरोध करने हेतु भी किया जा सकता है। हाल के वर्षों में खाप पंचायत द्वारा उपरोक्त प्रगतिशील संदर्भ में कई प्रयास किये जा रहे है।

56
खाप पंचायत एवं प्रतिष्ठा हत्या :
संभावित प्रश्न

57
प्रश्नः प्रतिष्ठा हत्या क्या है? क्या यह हमारे समाजिक/परम्परा संरक्षण हेतु उपयुक्त है? उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तरः PART-I : प्रतिष्ठा हत्या का अर्थ
PART-II : समीक्षा

1. इसके पक्षधरों का तर्क- यह परंपरागत सामजिक व्यवस्था के संरक्षण हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त है क्योंकि इससे संभव है-

58
- विवाह संबंधी निषेधों/परम्पराओं का संरक्षण
- सामाजिक प्रशासन व्यवस्था के रूप में परम्परागत जाति पंचायत एवं खाप पंचायत का संरक्षण
- परम्परागत पितृसत्तात्मकता का संरक्षण

59
2. उपरोक्त तीनों परम्परागत तत्व वर्तमान में अलोकतांत्रिक एवं गैर-कानूनी है और परम्परा में आधुनिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन आधुनिक समाज के निर्माण हेतु आवश्यक है।

60
3. इस आधुनिक परिवर्तन को अस्वीकार करके परम्परा के संरक्षण के नाम पर किसी की हत्या गलत है, और ऐसे लोगों को दण्ड देने का समर्थन SC ने भी किया है।

अतः निष्कर्ष है कि, परम्परा का संरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं परम्पराओं को, जिनमें मानव हित सर्वोपरि हो और जो आधुनिकता के मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके।

61

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में प्रतिष्ठा हत्या को रोकने के प्रयासों की समीक्षा कीजिए।
- "खाप पंचायत की वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्या आप इस मत से सहमत है?" उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
- "खाप पंचायत पितृसत्तात्मक समाज की अभिव्यक्ति है"। स्पष्ट कीजिए।

62

Dr. S. S. Pandey

भारत में जातिवाद
(Casteism in India)

63

भारत में जातिवाद

- जातिवाद का अर्थ
- जातिवाद के कारण
- जातिवाद के उन्मूलन हेतु प्रयास
- जातिवाद का स्वरूप
- जातिवाद के परिणाम
- समीक्षा एवं सुझाव

64

जातिवाद का अर्थ
(Meaning of Casteism)

65

भारत में जातिवाद, वह सीमित एवं संकीर्ण भावना (Limited and Narrow Feeling) है, जिसके तहत प्रत्येक कार्य, स्वजाति के हित को ध्यान में रख कर किये जाते हैं।

66

भारत में जातिवाद का स्वरूप
(Nature of Casteism in India)

67

- प्रशासन (Administration) मे जातिवाद
- राजनीति (Politics) में जातिवाद
- समाज (Society) में जातिवाद

68

भारत में जातिवाद के परिणाम-दुष्परिणाम
Consequences of Casteism in India

69

- जातीय शोषण संभव
- सामाजिक तनाव फलतः सामुदायिक सौहार्द्रता कमजोर
- राजनीतिक एवं सामाजिक तनाव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित
- राष्ट्रीय एकता (National Unity) को चुनौती
- भ्रष्टाचार (Corruption) को बढ़ावा
- विकास की प्रक्रिया (Development Process) बाधित

70

भारत में जातिवाद के कारण
Reasons of Casteism in India

71

- जाति के प्रति भावनात्मक लगाव की निरंतरता
- जजमानी प्रथा (Jajmani System) की समाप्ति
- 'संरक्षणात्मक भेदभाव' की नीति
- जातीय संगठनों की भूमिका
- जाति-राजनीति संबंध के नकारात्मक तत्व

72

जातिवाद के उन्मूलन हेतु प्रयास

Efforts to Eradicate Casteism

73

- संविधान में जाति सूचक शब्दों (Caste Related Words) का प्रयोग बंद कर दिया गया
- कानूनी कार्यवाही और विभिन्न मुकदमों की सुनवाई के दौरान वादी एवं प्रतिवादी का केवल नाम का प्रयोग
- हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा विभिन्न जातियों के बीच विवाह को मान्यता

74

- अंतर्जातीय विवाहों (Inter-Caste Marriages) को प्रोत्साहन
- व्यावसायिक निर्योग्यता की समाप्ति
- सभी नागरिकों को समानता का अधिकार (Right to Equality)
- कमजोर जातियों को आरक्षण
- गैर-सरकारी संगठन एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जातिवाद के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान

75

भारत में जातिवाद : संभावित प्रश्न

76

- जातिवाद आज समकालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्या है। इसके कारणों की चर्चा कीजिए और इसके उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में बताइए।
- जातिवाद क्या है? यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है? सोदाहरण समझाइए।
- "भारत में जातिवाद ने न केवल सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया है बल्कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी बाधित किया है।" चर्चा कीजिए।